

भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5242

जिसका उत्तर 02 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है।

12 चैत्र, 1947 (शक)

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना

5242. श्री के. गोपीनाथ:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अनुसंधान और विकास की उपेक्षा की जा रही है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसका औचित्य क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना शुरू की है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) देश के विकास और वित्तीय समावेशन में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) के योगदान का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अपने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से देश में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दे रहा है। इस कार्यक्रम के तहत, विभिन्न सामाजिक, औद्योगिक और रणनीतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (पीओसी) से लेकर सिस्टम विकास और तैनाती तक नई और स्वदेशी प्रौद्योगिकियां/सिस्टम/सॉफ्टवेयर/टूल्स विकसित किए जाते हैं। सरकार द्वारा क्षमता निर्माण, अनुसंधान के लिए ढांचागत सुविधाओं तथा शैक्षिक/अनुसंधान/स्टार्टअप व औद्योगिक स्तर पर उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।

सरकार विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से इस क्षेत्र में अनुसंधान प्रयासों को प्रोत्साहित कर रही है।

देश में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम (डीआईपी) के तहत अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एकुछ प्रमुख सरकारी पहलों का उल्लेख नीचे किया गया है: -

- **इंडिया एआई मिशन:** मंत्रिमंडल ने परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियों का लाभ सामाजिक प्रभाव के लिए, समावेश और नवाचार के लिए तथा भारत को एआई के क्षेत्र में विश्व में एक अग्रणी देश के रूप में स्थापित करने और एआई का उपयोग जिम्मेदारीपूर्ण और परिवर्तनकारी ढंग से करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम के रूप में 10,371.92 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी है। भारत की मंशा एआई मिशन कंप्यूटिंग संसाधनों तक पहुंच को लोकतांत्रिकरण करके, डेटा गुणवत्ता बढ़ाकर, घरेलू एआई विशेषज्ञता का पोषण करके, शीर्ष प्रतिभा को आकर्षित करके, उद्योग साझेदारी को बढ़ावा देकर, स्टार्टअप उद्यमों का समर्थन करके, सामाजिक रूप से प्रभावशाली एआई परियोजनाओं को बढ़ावा देकर और एआई में नैतिक प्रथाओं पर जोर देकर भारत के एआई परिदृश्य के भीतर जिम्मेदार और समावेशी विकास को बढ़ावा देने की है।
- **राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन:** मिशन को 2015 में लॉन्च किया गया था, ताकि उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग (एचपीसी) में एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दिया जा सके। एनएसएम के तहत, 30 से अधिक पेटा-फ्लॉप (1015) क्षमता वाले सुपर कंप्यूटरों को शैक्षणिक संस्थानों, आईआईएससी, आईआईटी आदि जैसे आरएंडडी प्रयोगशालाओं में स्थापित किया गया है, जिनकी मदद से 200 संस्थानों के 8000 से अधिक शोधकों को 94 लाख से अधिक एप्लिकेशन को डेवलप करने में सक्षम बनाया गया है। ये सुपर कंप्यूटर जीनोमिक्स, दवा की खोज, बाढ़ पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन और भूकंपीय डेटा प्रोसेसिंग में राष्ट्रीय स्तर के अनुप्रयोगों को विकसित करने में महत्वपूर्ण हैं।

मिशनकेतहतएचपीसीऔरएआईक्षेत्रोंमें 20,000 सेअधिकव्यक्तियोंकोप्रशिक्षितकियागयाहै।
 एचपीसीऔरएआईमें 'आत्मनिर्भर' (आत्मनिर्भरता) प्राप्तकरनेकेलिए,
 मिशनकेमाध्यमसेस्वदेशीसुपरकंप्यूटिंगउप-घटकोंयानीसर्वरबोर्ड, हाईस्पीडइंटरकनेक्ट,
 कम्प्लीटसॉफ्टवेयरस्टैक, डायरेक्टकॉन्टैक्टलिंक्डकूलिंग (डीसीएलसी)
 कूलिंगटेक्नोलॉजीआदिकाविकासकियागयाहै।

- **भाषिणी:** एमईआईटीवाईनेवर्ष 2022 में 495.51 करोड़रुपयेकेपरिव्ययसेमिशनडिजिटलइंडियाभाषिणी लॉन्चकियाहै। इसकाउद्देश्यडिजिटलमाध्यममेंभाषा कीबाधाओंकोदूरकरनेमेंमददकरनेकेलिएओपन सोर्समें 22 अनुसूचितभारतीयभाषाओंकेलिएभाषणऔरपाठअनुवादकेलिएमूलभाषाप्रौद्योगिकियोंकाविकासकरनाहै। भाषाप्रौद्योगिकीसमाधानोंकेप्रसारकेलिएएकराष्ट्रीयसार्वजनिकडिजिटलप्लेटफॉर्म <http://bhashini.gov.in> विकसितकियागयाहै।

- **सेमीकॉनडिजिटलप्रोग्राम:** डिजिटलइंडियाप्रोग्राम (डीआईपी) केअलावा, सरकारनेदेशमेंसेमीकंडक्टरऔरडिस्प्लेमैन्युफैक्चरिंगकोसिस्टमकेविकासकेलिए 76,000 करोड़रुपयेकेकुलपरिव्ययकेसाथ 'सेमीकॉनडिजिटलप्रोग्राम' कोभीमंजूरीदीहै। इस कार्यक्रमकाउद्देश्यसेमीकंडक्टरऔरप्रदर्शनविनिर्माणऔरडिजाइनपारिस्थितिकीतंत्रमेंनिवेशकरनेवालीकंपनियों कोवित्तीयसहायताप्रदानकरनाहै। यहवैश्विकइलेक्ट्रॉनिक्सऔरसेमीकंडक्टरमूल्यश्रृंखलाओंमेंभारतकीबढ़तीउपस्थितिकामार्गप्रशस्तकरताहै। उपर्युक्तकार्यक्रमकेअंतर्गतनिम्नलिखितचारस्कीमेंशुरूकी गईहैं:-

- i. भारतमेंसेमीकंडक्टरफैब्सकीस्थापनाकेलिएसंशोधितयोजना।
- ii. भारतमेंडिस्प्लेफैब्सकीस्थापनाकेलिएसंशोधितयोजना।
- iii. भारतमेंकंपाउंडसेमीकंडक्टर्स/सिलिकॉनफोटोनिक्स/सेंसर्सफैब/डिस्क्रीटसेमीकंडक्टर्सफैबऔरसेमीकंडक्टरअसेंबली, परीक्षण, मार्किंगऔरपैकेजिंग (एटीएमपी)/ओएसएटीसुविधाओंकीस्थापनाकेलिएसंशोधितयोजना
- iv. डिजाइनलिंकडप्रोत्साहन (डीएलआई) योजना।

- उपर्युक्तयोजनाओंकेअतिरिक्त, सरकारनेमौजूदासेमीकंडक्टरविनिर्माणसुविधा - सेमी-कंडक्टरप्रयोगशाला (एससीएल), मोहालीकाब्राउनफील्डफैबकेरूपमेंआधुनिकीकरणकरने को भीअनुमोदितकियाहैऔरसरकारद्वारासमय-समयपरकईनीतिगतहस्तक्षेपऔरयोजनाएंशुरूकीजातीहैं।

(ड): डिजिटलपब्लिकइन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) का आशयमूलभूतडिजिटलसिस्टमसे है। जोसार्वजनिकऔरनिजीसेवाओंकेनिर्बाधऔरकुशलवितरणकोसक्षमबनाताहै। डीपीआईभारतकेसामाजिक-आर्थिकविकासमेंएकपरिवर्तनकारीशक्तिरहीहै, जोवित्तीयसमावेशन, गवर्नेंसऔरआर्थिकविकासकोमहत्वपूर्णरूपसेबढ़ातीहै। भारतकेडीपीआईकोसिस्टममें**आधार,**

यूनिफाइडपेमेंट्सइंटरफेस (यूपीआई), डिजिलॉकरआदिजैसेप्रमुखप्लेटफॉर्मशामिलहैं। ग्रामीणक्षेत्रोंमेंडीपीआईकाविस्तारकरने,भारतकेलिएडिजिटलविभाजनकोदूर करने, वित्तीयसमावेशनमेंसुधारकरनेतथाआवश्यकसरकारीऔरवित्तीयसेवाओंतकपहुंचसुनिश्चितकरनेकी इन प्लेटफार्मों कीएकप्रमुखप्राथमिकतारहीहै।

इसलक्ष्यकोप्राप्तकरनेमेंकईपहलोंनेमहत्वपूर्णभूमिकानिभाईहै। इनपहलोंमेंआधारशामिलहै, जिसने 1.4 बिलियनलोगोंकोडिजिटलपहचानप्रदानकीहैऔरदैनिकआधारपरऔसतन 7 करोड़से अधिक लोगोंकेलिए ई-प्रमाणीकरणकीसुविधाप्रदानकीहै।

डिजिलॉकरजोडिजिटलरूपसेदस्तावेजोंऔरप्रमाणपत्रोंकोजारीकरनेऔरसत्यापनकेलिएएकमंचहै। डिजिलॉकरने 50 करोड़ से अधिकउपयोगकर्ताओंकोशामिलकियाहैऔर 924 करोड़दस्तावेजोंतकसहजपहुंचकीसुविधाप्रदानकररहाहै। उमंग -

सभीभारतीयनागरिकोंकेलिएकेंद्रसेलेकरस्थानीयसरकारीनिकायोंऔरअन्यनागरिककेंद्रितसेवाओंतकअखिलभारतीयडिजिटलसेवाओंतकपहुंचनेकेलिएएकीकृतमंच। वर्तमानमें, 207 केंद्रीय/राज्य/केंद्रशासितप्रदेशोंकेविभागोंकी

2,106 सेवाओंकोउमंगप्लेटफॉर्मपरऑन-बोर्डकियागयाहै। यूनिफाइडपेमेंटइंटरफेस (यूपीआई)
अग्रणीडिजिटलभुगतानमंचहै, औरयहदैनिकआधारपर 50 करोड़लेनदेनकीसुविधाप्रदानकररहाहै।
